BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Estd. 1926
Vol. XXXXVI | 11th March, 2015 | No. 5

गुलाब की पंखुड़ियों से चैम्बर में मनाया गया होली मिलन समारोह

राजस्थानी नृत्य का आनंद लेते माननीय खाद्य आपूर्ति एवं उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक, आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव श्री व्यास जी, माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, पूर्व उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, चैम्बर सदस्य श्री एस० पी० सिन्हा, माननीय विधायक श्री नीतिन नवीन, चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह एवं अन्य।

रंगों का त्योहार होली आपसी मतभेद को भूलकर भाईचारा निभाने, एक दूसरे को गले लगाने का अवसर है। इसी उद्देश्य से चैम्बर प्रांगण में प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी दिनांक 3 मार्च, 2015 को संध्या बेला में चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह की अध्यक्षता में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। चैम्बर अध्यक्ष ने गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर आगंतुकों का स्वागत किया। होली मिलन समारोह को और भव्य एवं आकर्षक बनाने हेतु जयपुर के ललित राणा डाँस ग्रुप के द्वारा राजस्थानी लोक नृत्य, झुमर, कलबेलिया का मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सुप्रसिद्ध भोजपुरी गायिका श्रीमती बिजली रानी के गीतों से लोगों का आनन्द और भी बढ़ गया। नृत्य एवं गीत से श्रोता मंत्रमुग्ध थे। इसके अतिरिक्त आगंतुकों के लिए स्वादिष्ट चटपटे व्यंजनों की भी व्यवस्था थी।

विशिष्ट अभ्यागतों में विधान परिषद के सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह, बिहार सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय खाद्य आपूर्ति एवं उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक, पूर्व उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, विपक्ष के नेता श्री नन्द किशोर यादव, विधायक श्री नीतिन नवीन, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद चन्द्रवंशी, आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव श्री व्यास जी, प्रधान सचिव, उद्योग श्री त्रिपुरारी शरण, सचिव, श्रम-संसाधन श्री एस० सिद्धार्थ, आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती एन० विजय लक्ष्मी सहित केन्द्र सरकार एवं बिहार सरकार के विभिन्न विभागों, बैंकों आदि के वरीय अधिकारी सम्मिलित थे। सभी आगंतुको को चुनरी का लाल साफा भी बांधा गया। प्रवेश द्वार पर सभी आगंतुकों का गुलाब जल छिड़क कर एवं इत्र लगाकर अभिनंदन भी किया गया ।

श्री ओ० पी० साह ने बताया कि रसायन मिश्रित रंग एवं गुलाल आँखों तथा

राजस्थानी नृत्य का आनंद लेते बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष श्री चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, माननीय खाद्य आपूर्ति एवं उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक, चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, महामंत्री श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल एवं अन्य।

विपक्ष के नेता श्री नंद किशोर यादव को गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। साथ में पूर्व कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं श्री श्याम सुन्दर हिसारिया।

माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी का गुलाब की पंखुड़ियों से अभिनन्दन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। साथ में पूर्व उपमुख्य मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी एवं चैम्बर सदस्य श्री एस० पी० सिन्हा एवं अन्य।

राजस्थानी लोक नृत्य प्रस्तुत करतीं नृत्यांगनाएँ।

त्वाचा के लिए नुकसानदेह होते हैं। इसलिए हमने कुछ प्राकृतिक चीज के उपयोग की सोची और गुलाब की पंखुड़ियों से बेहतर और कुछ हो नहीं सकता था। इसके अतिरिक्त रंगों में पानी की बर्बादी होती है जो हमारे लिए ईश्वर की एक अमूल्य भेंट हैं। कुछ लोग अबीर को लगाने से परहेज भी करते हैं। श्री साह ने कहा कि स्वाईन फ्लू के शहर में फैलने को लेकर भी हमें सलाह दी गयी थी कि पानी से किसी को भिंगोने से परहेज किया जाए। फूल स्वयं ही किसी समारोह के प्रतीक होते हैं। इसलिए हमने गुलाब की पंखुड़ियों से होली मनाने की सोची।

इस सम्पूर्ण आयोजन को सफल बनाने में पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश खेतड़ीवल के संयोजकत्व में पूर्व उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री मुकेश जैन ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय एवं श्री पी० के० अग्रवाल, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया, कोषाध्यक्ष डा० रमेश गाँधी, महामंत्री श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री मुकेश जैन एवं चैम्बर के सदस्य अपने परिवार सहित उपस्थित थे।

माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने दिनांक 28 फरवरी 2015 को आम बजट 2015–16 संसद में पेश किया

आम बजट की मुख्य विशेषताएं

अरूण जेटली
केन्द्रीय वित्त मंत्री

- पिछले नौ माह में भारतीय अर्थव्यवस्था की साख बढ़ी।
- भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र विकास के पथ पर प्रशस्त है।
- कमजोर वैश्विक आर्थिक वृद्धि के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के अधिकांश विकास संकेतक उन्नति के मार्ग पर।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में आर्थिक रूप से सशक्त राज्यों की समान रूप से सहभागिता।
- 7.4 प्रतिशत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के साथ अब विश्व की सबसे बड़ी और तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था बना भारत।
- दीर्घकालिक गरीबी उन्मूलन, राजेगार सृजन और दोहरे अंकों की विश्वसनीय आर्थिक विकास दर हासिल की गई।
- विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर सेवा के माध्यम से सरकार ने जनता का विश्वास हासिल किया।
- राज्यों के संसाधनों में वृद्धि के लिए पारदर्शी कोयला ब्लॉक नीलामी।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिये जन-धन, आधार और मोबाइल कारगर हथियार।
- मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई।
- मुद्रास्फीति को 6 प्रतिशत से कम रखने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व के साथ मौद्रिक नीति प्रारूप समझौता।
- अमृत महोत्सव वर्ष 2022 में स्वतंत्रता की 75 वी वर्षगांठ के लिये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में टीम इंडिया हेतु दृष्टिकोण।
- शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 करोड़ आवास।
- 24 घंटे बिजली, स्वच्छ पेयजल, एक शौचालय सड़क संपर्क की मूलभूत सुविधा।
- आजीविका के लिए परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार।
- महत्वपूर्ण गरीबी उन्मूलन।
- 2020 तक ऑफग्रिड सौर ऊर्जा सहित शेष 20 हजार ग्रामों का विद्युतीकरण।

- मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से भारत को विश्व के विनिर्माण केंद्र में परिवर्तित करना।
- युवाओं को रोजगार सृजन बनाने के लिए उद्यमिता की भावना का प्रोत्साहन और विकास।
- पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों का देश के अन्य भागों की तरह ही विकास करना।
- सरकार सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत की दर पर राजकोषीय घाटा लक्ष्य हासिल करने के लिए कृतसंकल्प है।
- कृषि उत्पादन हेतु दो महत्वपूर्ण निर्णायक कारकों मृदा और जल से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये गये।
- परंपरागत कृषि विकास योजना को पूरी तरह से सहायता प्रदान की जायेगी।
- प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना।
- चालू वित्त वर्ष के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण का लक्ष्य।
- ऋण देने में अंतरजातीय और अंतर जन जातीय उद्यमों को वरीयता।
- गांवों के 1,54000 केंद्रों वाले डाक नेटवर्क का सामान्य वित्तीय प्रणाली तक लोगों की पहुँच बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जायेगा।
- केवल 12 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये के दुर्घटना जन्य मृत्यु जोखिम को कवर करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
- पीपीएफ में लगभग 3 हजार करोड़ रुपये कर्मचारी भविष्यनिधि की संचित राशि में अनुमानत: 6 हजार करोड़ रुपये की अदावाकृत जमा राशि।
- सड़कों और रेल मार्गों के लिये परिव्यय में तीव्र वृद्धि।
- सरकारी क्षेत्र में पूंजीगत व्यय बढ़ाया गया।
- 20 हजार करोड़ रुपये के वार्षिक प्रवाह से राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि की स्थापना की जायेगी।
- प्लग और मोड में प्रत्येक 4 हजार मेगावाट वाली 5 नई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं।
- सोना खरीदने के लिए विकल्प के तौर पर सरकारी स्वर्ण बाण्ड स्कीम।
- भारतीय सोने के सिक्के बनाने की दिशा में कार्य करना, जिसके अग्र भाग में अशोक चक्र होगा।
- निर्भया निधि के लिए एक हजार करोड़ रुपये।
- आगमन पर वीजा सुविधा का विस्तार चरणबद्ध तरीके से 150 देशों तक करना।
- नवीकरणीय ऊर्जा, क्षमता को 2022 तक बढ़ाकर 1,75,000 मेगावाट तक करने का लक्ष्य।
- आंध्र प्रदेश की तरह बिहार और पश्चिम बंगाल को विशेष सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
- जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश और असम में नए एम्स की स्थापना। बिहार में एम्स जैसे दूसरे संस्थान की स्थापना।
- वित्त वर्ष हेतु आयोजना भिन्न व्यय 13,12,200 करोड़ रुपये अनुमानित।
- आयोजना व्यय 4,65,277 करोड़ रुपये अनुमानित।
- कुल व्यय 17,77,477 करोड़ रुपये अनुमानित है।
- रक्षा, आंतरिक सुरक्षा व्यय और अन्य आवश्यक व्यय की आवश्कता की पर्याप्त पूर्ति का प्रावधान किया गया।
- राज्यों को अंतरण 5,23,158 करोड़ रुपये अनुमानित।
- केन्द्र सरकार का हिस्सा 9,19,842 करोड़ होगा।
- आगामी वित्त वर्ष के लिये कर भिन्न राजस्व 2,21,733 करोड़ रुपये अनुमानित है।
- अगले वित्त वर्ष से चार वर्षों में कारपोरेट कर को 30 प्रतिशत से घटाकर 24 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- बचत सुगम बनाने के लिए व्यष्टि करदाता को छूट जारी।
- काले धन के सृजन और उसे छिपाने के कृत्य से प्रभावी और बलपूर्वक निपटा जायेगा।
- स्विस अधिकारियों के साथ बातचीत का एक प्रमुख सकारात्मक परिणाम सामने आया है।
- एंबुलेंस के चेसिस पर उत्पाद शुल्क को 24 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत किया गया।

'सूक्ष्म निधि मुद्रा बैंक' स्थापित होने से छोटे व नये उधमियों को होगा लाभ : चैम्बर अध्यक्ष

ओ० पी० साह, अध्यक्ष

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2015 को पेश आम बजट में आन्ध्र प्रदेश की भांति बिहार को विशेष सहायता देने का स्वागत किया है। साथ ही साथ लघु उद्यमियों के लिए सुक्ष्म निधि मुद्रा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है जिससे छोटे-छोटे व्यवसायी एवं फस्ट जेनेरेशन के उद्यमी फायदा उठा सकेंगे और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने बिहार के लिए AIMS की जैसी एक और संस्थान देने की माननीय केन्द्रीय वित्ती मंत्री की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने आगे कहा कि माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री की बजट घोषणा से ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार के चिरप्रतिक्षित मांगों की तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री के दिशा-निर्देश में माननीय वित्त मंत्री ने पहल शुरू कर दिया है।

श्री साह ने कहा कि खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को हतोत्साहित करने के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई है। इस पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश से देश के करोड़ों खुदरा व्यवसायी प्रभावित होंगे।

श्री साह ने कहा कि बजट भाषण में इस साल विकास दर 7.4% और मुद्रास्फीति 6% से कम रहने का विश्वास व्यक्त किया है, यह भी स्वागत योग्य है। सीमांत किसानों के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने की घोषणा भी स्वागत योग्य है क्योंकि इससे किसानों को अपने उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा आधारभूत संरचना को प्राथमिकता देते हुए इस क्षेत्र में पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ पाँच अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट जिसकी क्षमता 4000 मेगावाट की है, इससे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

उन्होंने कहा कि वेल्थ टैक्स समाप्त किया जाना स्वागत योग्य है लेकिन एक करोड़ की आय से उपर की आय पर 2% अधिभार लगाए जाने के बदले इसकी सीमा 10 करोड़ की जानी चाहिए थी। उन्होंने आगे कहा कि सर्विस टैक्स 12.36 की जगह 14% किए जाने से सेवा का कॉस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि पहले से ही काफी अधिक है। अत: उन्होंने माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि इस पर पुनरविचार किया जाए।

बजट 2015 में सस्ता-महँगा

महँगा

टेलीफोन, इंटरनेट, बिजली बिल, शराब, सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद, रेस्टोरेंट-होटल में खाना व ठहरना, क्रेडिट-डेबिट कार्ड का इस्तेमाल, ऑनलाइन रेल टिकट, पूर्ण निर्मित आयातित वाणिज्यिक वाहन, एसयूवी, हाईएंड मोटर साइकिलें, पार्लर, अस्पताल का बिल, ब्रांडेड कपड़े, जिम, केबल टीवी, मिनरल वाटर व बोतल बंद पेय, हवाई यात्रा, इंश्योरेंस पॉलिसी, यात्रा, ड्राईक्लीन, रेडियो टैक्सी सेवा, मोबाइल, सेट टॉप बॉक्स, घर खरीदना, प्लास्टिक बैग व बोरी, संगीत कार्यक्रम, चिट फंड व लॉटरी

सस्ता

एक हजार रुपये से अधिक मूल्य के चमड़े के फुटवियर, स्थानीय स्तर पर विनिर्मित मोबाइल फोन, एलईडी-एलसीडी पैनल्स, एलईडी लाइट और एलईडी लैंप, सोलर वॉटर हीटर, पेसमेकर, एंबुलेंस व एंबुलेंस सेवाएं, अगरबत्ती, माइक्रोवेव ओवन,, रेफ्रिजरेटर कम्प्रेसर, मूंगफली का मक्खन, पैकेटबंद फल व सब्जियां, संग्रहालय, चिड़ियाघर व राष्ट्रीय पार्क की यात्रा।

(साभार : आज, 1.3.2015)

- काले धन पर इसी सत्र में बनेगा नया कानून।
- कर प्रक्रियाएं सरल हुई।
- वार्षिक रूप से एक करोड़ से अधिक कर योग्य आय वाले धनिकों पर 2 प्रतिशत का अतिक्त अधिभार।
- घरेलू अंतरण मूल्य निर्धारण की प्रारंभिक सीमा पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये की गई।
- नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि में किया गया अनुदान आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अंतर्गत 100 प्रतिशत छूट।
- स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि में सीएसआर अंशदान के अलावा, अंशदानों के लिए 100 प्रतिशत की छूट।
- स्वच्छ पर्यावरण पहलों के लिए वित्त पोषण के लिए कोयला आदि पर स्वच्छ ऊर्जा उप कर को 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया गया।
- विद्युत चालित वाहनों और हाइब्रिड वाहनों पर लागू रियायती सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की समय सीमा एक साल के लिये बढ़ी।
- स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की छूट सीमा 15 हजार रुपये से बढ़कर 25 हजार रुपये, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 20 हजार से बढ़कर 30 हजार रुपये हुई।
- 80 वर्ष से अधिक की आयु वाले वरिष्ठ नागरिक जो स्वास्थ्य बीमा में कवर नहीं है, उन्हें चिकित्सीय व्यय के लिए 30 हजार रुपये की कटौती की अनुमति दी गई।
- विकलांग व्यक्तियों के लिये 25 हजार रुपये की अतिरिक्त कटौती।
- पेंशन निधि और नई पेंशन स्कीम में अंशदन के लिए 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट।
- कृषि उत्पाद दुलाई में सेवाकर छूट जारी।
- कृत्रिम हृदय को 5 प्रतिशत के बुनियादी सीमा शुल्क और सीवीडी से छूट।

(साभार : आज, 1.3.2015)

रेल बजट 2015-16

26 जनवरी 2015 को रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने 2015-16 का रेल बजट पेश किया

सुरेश प्रभु
रेल मंत्री

खास बातें : • 120 दिन पहले कराएं रिजर्वेशन • पांच मिनट में मिलेगी जनरल टिकट • कई भाषाओं में टिकट पोर्टल • सेना के जवानों को नहीं दिखाना पड़ेगा वारंट • 'एसएमएस अलर्ट' पर ट्रेन की लोकशन • ऑन लाइन बुक होगी व्हील-चेयर • 400 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा होगी • 200 नए आदर्श स्टेशन बनेंगे •17,000 वायो टॉयलेट लगाए जाएंगे • 108 ट्रेनों में ई-कैटरिंग सुविधा शुरू की जाएगी • 108 ट्रेनों में ई-कैटरिंग, स्थानीय भोजन उपलब्ध कराने पर जोर • सीनियर सिटीजन और प्रेग्नेंट के लिए लोअर बर्थ • 138 टोल फ्री नंबर पर अब आप दर्ज करा सकते हैं यात्रा में असुविधा, मेडिकल इमरजेंसी और केटरिंग संबंधी किसी भी समस्या के बारे में शिकायत • 182 टोल फ्री नंबर पर सुरक्षा संबंधी किसी भी समस्या के बार में अब आप दे सकते हैं रेलवे को जानकारी • जनरल कोच में मोबाइल चार्जिंग • स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत • महिला कोच में सर्विलांस कैमरे • 3438 बिना गार्ड वाले फाटक खत्म किए जाएंगे • RPF महिला कान्स्टेबलों की भर्ती और सिक्योरिटी अलर्ट मोबाइल ऐप जैसे उपायों का भी ऐलान • ट्रेन में मनोरंजन • कोच में ब्रेल लिपि

रेलमंत्री के इनोवेशंस : • रेलवे की जमीन पर 1,000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा • रेल बिल्डिंग की छतों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे • जिन सेंटर्स पर पानी का खर्च ज्यादा है वहा रिसाईक्लिंग प्लांट लगाया जाएगा • कचरे से ऊर्जा उत्पादन के लिए प्लांट लगाए जाएंगे • फॉरेन रेलवे टेक्नोलॉजी को-ऑपरेशन स्कीम लांच किया जाएगा। **(विस्तृत : आइनेक्स्ट, 27.2.2015)**

दीघा सड़क सेतु को अशोक राजपथ से जोड़ा जाएगा

दीघा सड़क सेतु से गाड़ियों के गुजरने का रास्ता साफ हो गया है। दीघा सड़क सेतु छह महीने में बन जाएगा, जबकि उसके बेहतर एप्रोच रोड में उपयोग होने वाला दीघा एक्स एलिवेटेड रोड (12 कि. मी.) बनने में दो साल लगेंगे। ऐसे में दीघा सड़क सेतु को चालू करने के लिए मात्र 2 कि. मी. लंबा एप्रोच रोड बनाकर उसे अशोक राजपथ (दीघा थाना के पास) में जोड़ा जा रहा है। **(दैनिक भास्कर, 27.2.2015)**

रेल बजट पर चैम्बर की प्रतिक्रिया

बिहार को मिलनी चाहिए थी नई ट्रेन

रेल बजट में यात्री सुविधा एव साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। हालाकि, बिहार को नई ट्रेनें मिलनी चाहिए थी। यह बड़ा प्रदेश है। यात्रियों की संख्या काफी अधिक है।

– सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष, बीसीसीआई

लंबित परियोजनाओं पर नहीं हुई बात

ऐसा प्रतीत होता है कि रेल बजट भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। परंतु राज्य की लंबित रेलवे की परियोजनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। इससे विकास प्रभावित होगा। हालांकि दीर्घ अवधि की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसका फायदा मिलेगा। **– मधुकर नाथ बरेरिया,** उपाध्यक्ष, बीसीसीआई

होना चाहिए था विशेष प्रावधान

रेल बजट में बिहार जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों का ध्यान नहीं रखा गया है। बिहार की लंबित परियोजनाओं के संबंध में बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए था। बिहार देश का एक प्रमुख राज्य है। **– डॉ० रमेश गांधी,** कोषाध्यक्ष, बीसीसीआई

उद्यमियों के लिए बजट फायदेमद

रेल बजट में यात्री भाड़े में किसी तरह की वृद्धि नहीं करने से यात्रियों एवं उद्यमियों को काफी राहत मिलेगी। गड़ियों एवं स्टेशनों पर साफ-सफाई की व्यवस्था पर और अधिक खर्च करने का प्रावधान होना चाहिए था, जो नहीं है। माल भाड़ा में भी मामूली वृद्धि हुई है। इससे वस्तुओं की कीमत पर परिवहन लागत में वृद्धि नहीं होगी।

– ओ. पी. टिबड़ेवाल, महामंत्री, बीसीसीआई

(साभार : दैनिक जागरण, 27.2.2015)

बहुत सहज है आधार संबंधी दिक्कतों को दूर करना

आधार संबंधी दिक्कतों को लेकर इस समय अधिकांश लोग परेशान हैं। किसी का आधार कार्ड नहीं पहुँचा है तो किसी के नाम की स्पेलिंग में गलती हो गई है। कुछ लोगों को निबंधन रसीद भी गुम हो गई है। ऐसी तमाम दिक्कतों को दूर करने के उपाय भी हैं।

नहीं पहुँचा आधार कार्ड : अधिकांश लोग आधार कार्ड के लिए निबंधन करा चुके हैं, लेकिन एक से डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी उनके घर पर आधार कार्ड नहीं पहुँचा है। ऐसे लोग यूनिक आइडेन्टिफिकेशन ऑथरिटी ऑफ इंडिया (यूआइडीएआइ) की वेबसाइट (एचटीटीपीएस://आरईएसआइडीईएनटी डॉट यूआइडीएआइ डॉट एनईटी डॉट आइएन) पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर निबंधन संख्या (दिन, महीना, साल, समय के साथ) डालकर इसे डाउन -लोड किया जा सकता है।

गलत हो गया है नाम : अगर आधार कार्ड में आपका नाम गलत हो गया है तो इसे सही किया जा सकता है। इसे आप ऑनलाइन (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटयू आइडीए आइडॉटजीओवीडॉटआइन/यूपीडीएटीई-वाइओयूआर-एएडीएचएएआर-डीएटी-एडॉटएचटीएमएल) शुद्ध कर सकते है। ध्यान रखें कि सही करने के लिए आपको वैध दस्तावेज भी अपलोड करना होगा। इस प्रक्रिया के 15 दिन बाद आपको एसएमएस यह जानकारी मिल जाएगी कि सुधार किया गया अथवा नहीं।

पति की जगह पिता का नाम : अगर किसी महिला के आधार कार्ड में पिता का नाम है और वह इस जगह पर पति नाम चाहती है, तो यह भी बदलाव इसी वेबसाइट के जरिए संभव है।

नाम परिवर्तन संभव नहीं : अगर कोई अपना पूरा नाम बदलना चाहता है तो यह संभव नहीं है। मसलन, अगर रमेश नाम का व्यक्ति सुरेश करना चाहता है तो यह संशोधन नहीं हो सकता।

रखिए जानकारी : • नाम गलत है तो इसे संशोधित करने का भी विकल्प • निबंधन की रसीद भूल जाने पर भी मिल सकती है मदद • **फिर भी न बने बात तो :** टॉल फ्री नंबर18003001947 • **अन्य नंबर :** 06576450145 (दूसरा नंबर टॉल फ्री नंबर नहीं है) **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 26.2.2015)**

रेल बजट में बिहार

रेल बजट में बिहार की परियोजनाओं के लिए 5000 करोड़ से अधिक की धन राशि मंजूर,पिछली बार 981 करोड़ मिले थे

राजेन्द्र पुल के समानांतर बनेगा एक और रेल पुल

प्रभु की इच्छा : हमें इतना ही मिला : • मुंगेर को 150 व दीघा को 300 करोड़, इसी साल होंगे पूरे • बक्सर-मुगलसराय के बीच बनेगी तीसरी लाइन, सर्व होगा • नई लाइन, आमान परिवर्तन की 6 व दोहरीकरण की 11 परियोजनाएं मंजूर • 75 आरओबी और आरयूबी का भी निर्माण होगा • बिहार होकर गुजरेगी 200 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन • रक्सौल-नरकटियागंज आमान परिवर्तन से दिल्ली के लिए नया मार्ग • सहरसा-पूर्णिया आमान परिवर्तन से पटना के लिए नया मार्ग • रक्सौल-नरकटियागंज आमान परिवर्तन से दिल्ली के लिए नया मार्ग • सहरसा-पूर्णिया आमान परिवर्तन से पटना के लिए नया मार्ग • रेल बजट में बिहार के लिए पाँच हजार करोड़ रुपए की योजनाएं मंजूर

बिहार के लिए कितनी धनराशि : • मोकामा पुल - 893 करोड़ • तीन अन्य पुल - 480 करोड़ • दोहरीकरण व अन्य लाइन - 1725 • यात्री सुविधा - 446 करोड़ • आरओबी व अन्य - 1500 करोड़।

पुलों के लिए : • मुंगेर - 150 करोड़ रुपए • दीघा - 300 करोड़ रुपए • कोसी - 30 रुपए

दोहरीकरण की परियोजना : • सोनपुर-हाजीपुर : 3 करोड़ • कुरसेला-सेमापुर : 2 करोड़ • साहेबगंज-पीरपैंती : 55 करोड़ • महेशखूंट-थाना बिहपुर : 50 करोड़ • बेगूसराय-खगड़िया : 80 करोड़ • किऊल-गया को : 36 करोड़ • हाजीपुर-बछवारा को : 16 करोड़ • समस्तीपुर-दरभंगा को : 09 करोड़ • तिलरथ-बेगूसराय : 4 करोड़ • तारेगना-जहानाबाद : 4 करोड़ • मानसी-महेशखूंट : 2 करोड़ • कटरिया-कुरसेला : 2 करोड़ • मोकामा पुल : 20 करोड़ • पीरपैंती-भागलपुर : 150 करोड़ • महेशखूंट-थाना बिहपुर : 25 करोड़ • हाजीपुर-रामदयालु नगर : 40 करोड़

रेल लाइन : सकरी-हसनपुर: 5 करोड़ • खगड़िया-कुशेश्वर : 15 करोड़ • हाजीपुर-सुगौली वाया वैशाली: 80 करोड़ • देवघर-सुल्तानगंज : 30 करोड़ • रामपुर-मंदारहिल : 75 करोड़ • पीरपैंती-जसीडीह : 10 करोड़ • महाराजगंज-मशरख : 60 करोड़ • आरा-सासाराम : 1 करोड़ • मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी : 5 करोड़ • राजगीर-हिसुआ: 1 करोड़ • फतुहा-इस्लामपुर-दनियावा-बिहारशरीफ : 2 करोड़ • सीतामढ़ी-जयनगर- निर्मली : 1 करोड़ • गया-बोधगया-चतरा-नटेसर : 1 करोड़ • नवादा-लक्ष्मीपुर : 50 लाख।

आमान परिवर्तन : • मानसी-सहरसा-पूर्णिया : 75 करोड़ • जयनगर- दरभंगा -नरकटियागंज : 50 करोड़ • सकरी-लौकहा बाजार-निर्मली एवं सहरसा-फारबिसगंज को : 42 करोड़ • जयनगर-विजलपुरा-वाडीदास को : 44 करोड़

छोटे प्रोजेक्ट के लिए इतने रुपए का प्रावधान (यातायात से जुड़ी घोषणाएं एवं राशि) : • पावापुरी रोड-सिलाव पारण स्टेशन : 1.25 करोड़ • बंका घाट-खुसरूपुर करौटा-अथमलगोला लूप लाइन : 3 करोड़ • नंदनी-लगुनिया तीन लाइन पारण स्टेशन में परिवर्तन : 15 करोड़ • बख्तियारपुर फ्लाइओवर : 0.7 करोड़ • टेक बिगहा लेमुआबाद पारण स्टेशन : 2 करोड़ • किशनपुर रामभद्र व हदयघाट या सैंडहंप सहित तीसरी लाइन : 1.25 करोड़ • न्यू मुजफ्फरपुर टर्मिनल स्टेशन : 3 करोड़ • सदीशोपुर (नेउरा-बिहटा) में मध्यवर्ती ब्लॉक खंड : 1 करोड़ • बेतिया, बापूधाम-मोतिहारी, चकिया, लहेरियासराय व रक्सौल यार्ड नान गुड्स टर्निंग लाइन का शंट सिग्नल सहित रनिंग लाईन में परिवर्तन : 1.25 करोड़ • कुचमान नई डाउन कॉमन लूप : 2.5 करोड़ • गया लाइन संख्या आठ एवं नौ पर पूरी लंबाई का प्लेटफॉर्म : 0.5 करोड़ • सेमरा व रामगढ़वा सैंडहंप सहित तीसरी लाइन : 1 करोड़ • करजरा व करौटा पाटनर पारण स्टेशन : 5 करोड़ • झाझा तीसरी लूप और अप लाइन : 4 करोड़ • वंशीपुर डाउन कॉमन लूप : 3 करोड़ • कृष्णशिला दो अतिरिक्त लूप लाइन : 2.7 करोड़ • बिहारशरीफ तीसरी लूप लाइन : 1 करोड़ • महेदिया अतिरिक्त लूप : 2 करोड़ • शेखपुरा अतिरिक्त लूप : 1.25 करोड़ • पहलेजा का बी श्रेणी स्टेशन के रूप में विकास : 1 करोड़ • भभुआ रोड यात्री टर्मिनल : 1 करोड़

(साभार : दैनिक भास्कर, 27.2.2015)

13 मंत्रियों को 14 विभागों का मिला अतिरिक्त प्रभार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट के 13 मंत्रियों को 14 विभागों का अतिरिक्त प्रभार दिया है। 14 विभागों के बंटवारे के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास मुख्य रूप से मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, गृह, सामान्य प्रशासन समेत ऐसे विभाग जो 22 मंत्रियों के बीच आवंटित नहीं हैं, वे भी मुख्यमंत्री के पास हैं।

मंत्री व अतिक्ति प्रभार : विजय कुमार चौधरी: कृषि व सूचना जन संपर्क • **लेसी सिंह :** आपदा प्रबंधन • **नरेंद्र नारायण यादव :** कानून • **जय कुमार सिंह :** आईटी • **राजीव रंजन सिंह :** विज्ञान व प्रावैधिकी • **दामोदर रावत :** पीएचडी • **रमई राम :** अनुसूचित जाति जनजाति • **पी. के. शाही :** शिक्षा • **विजेन्द्र यादव :** ऊर्जा • **श्रवण कुमार :** ग्रामीण विकास • **रामलखन राम रमण :** कला संस्कृति • **अवधेश प्र. कुशवाहा:** नगर विकास • **श्याम रजक :** उद्योग।

(साभार : प्रभात खबर, 25.2.2015)

ढुलाई भाड़ा बढ़ने से अनाज, दाल व सीमेंट होंगे महंगे

अनाज, दाल, सीमेंट, स्टील आदि के दाम बढ़ सकते हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इनकी ढुलाई का भाड़ा बढ़ा दिया है। कुल 12 कमोडिटी पर 0.8 फीसदी से 10 फीसटी तक बढ़ोत्तरी हुई है। कोयले की ढुलाई महंगी होने से बिजली भी मंहगी हो सकती है।

डीजल पर भाड़ा एक फीसदी और लाइमस्टोन, डोलोमाइट व मैग्नीज पर 03 फीसदी कम हुआ है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। माल भाड़ा बढ़ने से सरकार को 4,000 करोड़ रूपये अतिरिक्त कमाई की उम्मीद है।

• रसोई गैस, केरोसिन : दाम बढ़ेंगे • यूरिया : दाम पर असर नहीं • कोयला : असर कई जगह • सीमेंट: बोरी 10 रुपए तक महंगी होगी • आयरन-स्टील : मामूली इजाफा • मूँगफली तेल मंहगा होगा • अनाज एवं दालें-दाम बढ़ना तय।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 27.2.2015)

पटना आना-जाना होगा आसान

रेल बजट में पटना के यातायात के लिए बहुत कुछ खास है। सचिवालय हॉल्ट क्रॉसिंग पर आरओबी से राजधानी के कई इलाके के लोगों को जाम से छुटकारा मिलेगा। वहीं दीघा रेल सह सड़क पुल बन जाने से राजधानी आने-जाने वाले उत्तर बिहार के लोगों को सहूलियत होगी। अभी उन्हें गांधी सेतु पर घंटों जाम से जूझना पड़ना है। राजेन्द्र सेतु के दोहरीकरण से ट्रेनों की लेटलतीफी पर भी विराम लगेगा। बख्तियारपुर में भी फ्लाई ओवर बनाने के लिए राशि स्वीकृत हुई है।

सचिवालय हॉल्ट आरओबी को मिली स्वीकृति : रेल बजट में पटना सहित बिहार के कई रेलवे क्रासिंग पर आरओबी (रेल ओवरब्रिज) के लिए बजट जारी हुआ है। पटना-सचिवालय हॉल्ट रेलवे क्रॉसिंग (समपार संख्या 30) पर 29 करोड़ रूपए से आरओबी स्वीकृत हुआ है। रेल बजट में इस वर्ष के लिए पाँच लाख रुपए जारी हुए हैं। इसके अलावा बिहार के 37 क्रासिंग के लिए धनराशि मुहैया कराई गई है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 27.2.2015)

वाणिज्य कर विभाग के निशाने पर व्यापारी

पिछले दिनों वाणिज्य कर विभाग ने जिन व्यापारियों का माल रेलवे की लीज बोगी से जब्त किया था, उन सभी पर जल्द ही छापेमारी होगी। विभान ने सभी लीज होल्डरों से सामान मंगवाने वाले व्यापारियों का नाम पूछना शुरू कर दिया है। अगर कोई लीज होल्डर व्यापारियों का नाम बताने से इंकार करता है, तो उनपर प्राथमिकी दर्ज होगी।

विभाग के अधिकारी ने बताया कि पिछले एक महीने में विभिन्न ट्रेनों की लीज बोगियों से लगभग पाँच करोड़ रुपये का बिना परमिट का सामान जब्त किया गया है। इनमें सबसे अधिक रेडिमेड कपड़े हैं। ऐसे में विभाग ने सबसे पहले रेडिमेड कपड़ा व्यापारियों पर कार्रवाई करने की योजना बनायी है। हालांकि फुटवेयर, हार्डवेयर एवं प्लास्टिक के सामान मंगवाने वाले व्यापारियों पर भी विभाग की नजर है। विभाग के वरीय अधिकारी ने बताया कि विभाग ने बिहार के कई रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन की लीज बोगी में छापेमारी कर लगभग डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक का सामान जब्त किया था।

(साभार : हिन्दुस्तान, 25.2.2015)

14वें वित्त आयोग की सिफारिशें

केंद्र ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए करों में राज्यों को मिलनेवाली हिस्सेदारी में 10 फीसदी की बड़ी वृद्धि की है। इससे राज्यों के पास अधिक धन पहुँचेगा और विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए उनके पास अधिक वित्तीय स्वतंत्रता होगी। प्रधानमंत्री ने इसे 'को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म' को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बताया है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी सही तसवीर बजट में दिखेगी और यदि सामाजिक योजनाओं का भार राज्यों पर डाला गया तो पिछड़े राज्यों की परेशानी बढ़ सकती है।

राज्यों की हिस्सेदारी (फीसदी) में

राज्य	नयी सिफारिश	पहले	राज्य	नयी सिफारिश	पहले
आंध्र प्रदेश	4.305	6.937	मणिपुर	0.617	0.451
अरुणाचल प्रदेश	1.37	0.328	मेघालय	0.642	0.408
असम	3.311	3.628	मिजोरम	0.46	0.269
बिहार	9.665	10.917	नागालैंड	0.498	0.314
छत्तीसगढ़	3.08	2.47	ओड़िशा	4.642	4.779
गोआ	0.378	0.266	पंजाब	1.577	1.389
गुजरात	3.084	3.041	राजस्थान	5.495	5.853
हरियाणा	1.084	1.048	सिक्किम	0.367	0.239
हिमाचल प्रदेश	0.713	0.781	तमिलनाडू	4.023	4.969
जम्मू-कश्मीर	1.854	1.551	तेलंगाना	2.437	.....
झारखंड	3.139	2.802	त्रिपुरा	0.642	0.511
कर्नाटक	4.713	4.328	उत्तर प्रदेश	17.959	19.677
केरल	2.5	2.341	उत्तराखंड	1.052	1.12
मध्य प्रदेश	7.548	7.12	पश्चिम बंगाल	7.342	7.264
महाराष्ट्र	5.521	5.199			

किस राज्य को मिलेगी कितनी रकम

14वें वित्त आयोग और इसके पहले के आयोग द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान का अंतर

राज्य (रुपये करोड़ में)	13वां वित्त आयोग	14वां वित्त आयोग	परिवर्तन (%) में
आंध्र प्रदेश	13,532.3	36,588.89	170.38
अरुणाचल प्रदेश	4,348.2	1,321.95	-69.59
असम	5,212.1	12,053.12	131.25
बिहार	14,602.8	26,026.07	78.22
छत्तीसगढ़	6,175.5	8,028.04	29.99
गोआ	516.2	371.62	-28
गुजरात	9,682.9	18,546.12	91.53
हरियाणा	4,270.8	7,492.46	75.43
हिमाचल प्रदेश	10,364.4	43,810.57	322.7
जम्मू-कश्मीर	20,255.9	65,703.37	224.36
झारखंड	7,238.4	9,770.29	34.97
कर्नाटक	11,601.4	16,520.54	42.4
केरल	6,371.5	18,119.96	184.39
मध्य प्रदेश	13,324.5	23,095.95	73.33
महाराष्ट्र	16,302.8	34,824.54	113.61
मणिपुर	7,026.3	10,700.74	52.29
मेघालय	3,923.9	1,921.52	-51.03
मिजोरम	4,904	12,387.21	152.59
नागालैंड	9,191.3	18,651.48	102.92
ओड़िशा	9,658.8	14,339.79	48.46
पंजाब	5,540.3	8,482.07	53.11
राजस्थान	12,949.8	23,630.75	82.48
सिक्किम	1,058.8	353.39	-66
तमिलनाडू	11,366.9	20,385.74	79.34
तेलंगाना	10,127.18	नया राज्य	.....
त्रिपुरा	5,716.1	5,815.78	1.74
उत्तर प्रदेश	26,742.9	49,381.77	84.65
उत्तराखंड	4,063.0	3,740.52	-7.93
पश्चिम बंगाल	12,638.0	35,160.54	178.21
कुल	**2,68,581.7**	**5,37,354.2**	**100.07**

(स्रोत : वित्तआयोग)

अन्य बड़ी सिफारिशें : • 2.87 लाख करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है स्थानीय निकायों को • 1.94 लाख करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है कम राजस्व घाटे वाले राज्यों को • 100 फीसदी कंपेनशेसन पहले तीन वर्षों में, 75 फीसदी चौथे व 50 फीसदी पाँचवें वर्ष में • 3 फीसदी राजस्व घाटा का लक्ष्य वर्ष 2016-17 से • 100 फीसदी बिजली मुहैया कराने का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से • सब्सिडी की रकम के भुगतान में देरी करने पर राज्यों को जुर्माना।

(प्रभात खबर, 26.2.2015)

बिहार के घाटे की भरपाई करे केंद्र

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25.02.2015 को 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि आयोग की अनुशंसा बिहार के लिए न्यायसंगत नहीं है। अनुशंसा से बिहार पर कुप्रभाव पड़ रहा है। बिहार के योजना आकार पर इसका असर पड़ेगा और प्रति वर्ष हम जो विकास की दर हासिल कर रहे हैं वह कम हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह केंद्र से अनुरोध करते हैं कि वित्त आयोग की अनुशंसा पर बिहार को जो घाटा हुआ है वह उसकी भरपाई करे।

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को केंद्र सरकार ने मान लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस संबंध में पत्र भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस संबंध में उनसे बात भी की है। चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा से केंद्रीय करों में दस प्रतिशत की राशि जरूर बढ़ेगी पर इसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। केंद्रीय योजनाओं की संख्या में कटौती होने से उसके तहत मिलने वाला केंद्रांश तो खत्म हो ही गया, साथ ही अब योजनाओं के मद में केंद्र से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अन्य ग्रांट तथा बीआरजीएफ के तहत बिहार को जो अतिरिक्त राशि मिलती थी उसे भी बंद कर दिया जाएगा। गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले के तहत मिलने वाली राशि भी खत्म हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में जो राशि बिहार को मिली थी उससे भी कम पैसा वित्तीय वर्ष 2015-16 में मिलेगा। तेरहवें वित्त आयोग में बिहार को 10.9 प्रतिशत हिस्सेदारी मिली थी। चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा से यह घटकर 9.6 प्रतिशत हो जाएगी। बिहार को बीआरजीएफ के तहत राशि मिलने का प्रावधान संसद में पारित बिहार रिआर्गनाइजेशन एक्ट के तहत है। अगर केंद्र सरकार बीआरजीएफ की राशि रोकती है तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है। पूर्व में एक बार 12 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर कुछ राज्यों को घाटा हुआ था तो आंध्र प्रदेश ने इस मामले को उठाया था। तत्कालीन एनडीए सरकार ने तब उन राज्यों को विशेष सहायता उपलब्ध कराई थी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 26.2.2015)

12 मार्च को पेश होगा बिहार का बजट

चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने 25.02.2015 को अपनी कैबिनेट की पहली बैठक की। इसमें विधान सभा के बजट सत्र के बारे में निर्णय लिया गया। 11 मार्च से शुरू होने वाला बजट सत्र 22 अप्रैल तक चलेगा। 11 को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री विश्वासमत हासिल करेंगे। 11 को ही राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। 12 मार्च को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बिहार का बजट पेश होगा। फिर वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी सदन में पेश की जाएगी। 13 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद व सरकार का उत्तर होगा। 18 मार्च को लेखानुदान लिया जाएगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 26.2.2015)

15 जिलों में लगेगी उद्योग प्रदर्शनी

वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर है। इस कारण सभी विभाग लक्ष्य पूरा करने में जुट गये हैं। उद्योग विभाग ने भी 15 जिलों में उद्योग मेला लगाने का टारगेट फिक्स कर दिया है। विभाग ने मात्र 15 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। जिन 15 जिलों में उद्योग मेला और प्रदर्शनी नहीं लगी है, उनमें 11 जिलों में उद्योग विभाग जबकि शेष चार जिलों में खादी बोर्ड मेला व प्रदर्शनी लगायेगा। पटना, सारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, नालंदा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी और रोहतास में उद्योग मेला सह प्रदर्शनी लगानी है। तीन दिवसीय उद्योग मेला सह प्रदर्शनी में उद्योगों के विकास पर सेमिनार भी होगा। भागलपुर, मधुबनी, दरभंगा और मुंगेर में रेशम बुनकरों के उत्पाद और मधुबनी पेंटिंग वाले उत्पादों की भी प्रदर्शनी लगेगी।

(साभार : प्रभात खबर, 26.2.2015)

1. **व्यापार अथवा पेशे के लाभ तथा अभिलाभ के अन्तर्गत कटौतियाँ**
किसी भी करदाता की व्यापार अथवा पेशे की कर योग्य आय की गणना करते समय इस बात का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है कि "व्यापार अथवा पेशे के लाभ तथा अभिलाभ" शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना करते समय कौन-कौन सी कटौतियाँ उपलब्ध हैं एवं उन कटौतियों को दावा करने के लिए आवश्यक शर्त्तें कौन सी हैं। इस जानकारी के आधार पर करदाता अपनी आय की गणना करते समय अपना कर नियोजन इस प्रकार से कर सकता है कि अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत कटौतियों का अधिकतम उपयोग कर कानूनी रूप से कर की बचत की जा सके।
2. **आयकर अधिनियम के अंतर्गत दण्ड (Penalty) तथा अभियोजन (Prosecution)**
आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चूकों के लिए किसी भी करदाता पर पेनाल्टी लगाई जा सकती है एवं कुछ निश्चित परिस्थितियों में कर दाता द्वारा किये गये अपराधों के लिए आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही भी की जा सकती है।
करदाता को कभी दण्ड या अभियोजन की कार्यवाही का सामना न करना पड़े इसके लिए करदाता को प्रावधानों की जानकारी आवश्यक है।
उपर्युक्त के पूर्ण विवरण हेतु चैम्बर से सम्पर्क करें।

(साभार : टैक्स पत्रिका, फरवरी, 2015)

शहर में 35 फीसदी बिजली हो रही बर्बाद

• 450 मेगावाट तक शहर में बिजली सप्लाई • 158 मेगावाट बिजली की होती है बर्बादी • 35 फीसदी ट्रांसमिशन-डिस्ट्रीब्यूशन लॉस •24 फीसदी बिजली की चोरी राजधानी में • 22 फीसदी बिजली की चोरी राष्ट्रीय स्तर पर • 09 फीसदी बिजली की चोरी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर • 12 से 15 फीसदी तक ही बिजली बर्बादी की सीमा होनी चाहिए • 05 करोड़ में हर रोज राजधानी में खरीदी जाती है बिजली

बिजली कंपनी का पक्ष : कंपनी के वरीय अधिकारियों के मुताबिक शहर में बिजली की बर्बादी मे काफी कमी आयी है। पाँच-छह साल पहले 50 से 52 फीसदी तक बिजली की बर्बादी होती थी। यह कंपनी के उपायों से संभव हुआ है। मौजूदा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में इसमें और कमी लाने के उपाय हो रहे हैं। सरकारी भवनों में प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू है। आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा रहा है। इससे काफी कमी आएगी।

बिजली बर्बादी की वजह : • मीटर बाइपास और टोका फंसा चोरी • बिजली सप्लाई की जर्जर व्यवस्था • कम शक्ति के तार, ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण • बार-बार तार टूटना और ट्रांसफार्मरों का जलना प्रमुख कारण • दिन में कई दफे शटडाउन और ब्रेकडाउन से बिजली स्थिति गंभीर • सबस्टेशनों का आधुनिकीकरण नहीं • पुराने तकनीक के ब्रेकर और रिले।

बिजली की बर्बादी 15 फीसदी पर लाएं : ऊर्जा विशेषज्ञ बीएल यादव के मुताबिक बिजली की बर्बादी 12 से 15 फीसदी तक ही रहनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर 22 फीसदी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महज 9 फीसदी ही बिजली की बर्बादी हो रही है। बर्बादी कम हो, इसके लिए लोगों को भी जागरूक करना होगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 25.2.2015)

पटना की ट्रैफिक व्यवस्था बदलेगी

दो महीने बाद राजधानी की यातायात व्यवस्था बदली-बदली नजर आएगी। पटना पुलिस उन इलाकों के लिए विशेष योजना बना रही है जहाँ ट्रैफिक जाम अधिक है। योजना के तहत पटना की सभी महत्वपूर्ण सड़कों का खाका बनाया गया है। कई जगहों पर कट बंद कर दिए जाने की भी बात चल रही है। यूटर्न, आगे मोड़, दाहिने मुड़िये या आगे की रास्ता संकीर्ण है - जैसे ट्रैफिक सिंबल लगाए जाएंगे।

जाम वाली जगहों पर फोकस : डाकबंगला, इनकम टैक्स, आर ब्लॉक, हड़ताली मोड़, बोरिंग रोड चौराहा, गाँधी मैदान गोलम्बर आदि जगहों पर सबसे अधिक जाम लगता है। खासकर पिक आवर में तो गाड़ियाँ रेंगने लगती हैं। पटना पुलिस इन जगहों का बारीकी से अध्ययन कर रही है। इन जगहों पर पेंटिंग का काम दोबारा किया जाएगा। हाईकोर्ट मोड़ के पास बेली रोड और बोरिंग रोड के लिए डिवाइडर चौड़ा किया जाएगा। ट्रैफिक ड्यूटी में लगे होमगार्ड के 380 जवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तीन दिवसीय प्रशिक्षण चार मार्च से शुरू होगा। उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के विशेषज्ञ प्रशिक्षण देंगे।

खाका तैयार : • ट्रैफिक जवानों को मिलेगा यातायात नियमों का प्रशिक्षण • पटना की सभी महत्वपूर्ण सड़कों का बन रहा खाका

बढ़ेंगे पुलिस बल : • ट्रैफिक जवान-700 • हवलदार -150 • सब इंस्पेक्टर-50 • डीएसपी-4 • एडीसी-1

राजधानी की सड़कों पर लोड : 2005 में राजधानी में सवा लाख वाहन थे। अब सात लाख वाहन आ गये हैं। इसमें पचास हजार से अधिक वाहन ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों और जिलों से आते-जाते हैं। चार पहिया वाहनों की संख्या सबसे अधिक बढ़ी है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 27.2.2015)

मालसलामी में आधुनिक बस डिपो

पटना के मालसलामी में अंतरराज्यीय स्तर का बस डिपो बनेगा। होली के बाद इसका काम शुरू होगा। अक्टूबर 2016 तक यहाँ से बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। बिहार के महत्वपूर्ण शहरों के अलावा अन्य राज्यों की बसें यहीं से खुलेंगी। बस अड्डे पर लगभग दो हजार बसों के ठहरने की क्षमता होगी।

• लगभग 2000 बसों के ठहरने की होगी क्षमता • बुडको ने आमंत्रित किया टेंडर होली के बाद शुरू होगा काम • 4.99 करोड़ से सात हजार वर्गमीटर में बनेगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 27.2.2015)

डेबिट कार्ड से जमा होंगे अब वाहन कर

सभी बैंकों में शुरू होगा ई-पेमेंट सिस्टम, अभी भारतीय स्टेट बैंक में ही यह सुविधा प्राप्त

अगले वित्तीय वर्ष से वाहन टैक्स डेबिट कार्ड से जमा होंगे। इस सिस्टम के तहत वाहन मालिक देश के किसी भी कोने में बैठकर वाहन टैक्स जमा कर सकते हैं। साथ ही सभी बैंकों में अब ई-पमेंट से वाहन टैक्स का भुगतान होगा। वित्त विभाग ने इसकी अनुमति दे दी है। परिवहन विभाग अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजेगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही यह सेवा शुरू हो जाएगी। अभी वाहन मालिक सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक में ई-पेमेंट के माध्यम से टैक्स जमा कर रहे हैं। वर्ष 2012 में सबसे पहले पाँच शहरों पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया व पूर्णिया में ई-पेमेंट सिस्टम लागू किया गया था। इसके बाद पूरे राज्य में इसे लागू कर दिया गया था। परिवहन विभाग की योजना है कि राज्य के सभी बैंकों में ई-पेमेंट सिस्टम को लागू किया जाए। वाणिज्यिक बैंकों के बाद इस सिस्टम को निजी बैंकों में भी लागू करने पर विचार चल रहा है। वर्ष 2012 में परिवहन विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ यह करार किया था।

(साभार : हिन्दुस्तान, 27.2.2015)

दस रुपए के नए नोट जारी करेगा रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक दस रुपए के नए नोट जाटी करेगा। नए नोट महात्मा गाँधी श्रृंखला 2005 के तहत जारी किए जाएंगे। इस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम जी राजन का हस्ताक्षर एवं इंसेट में लेटर एन, रूपये का चिह्न अंकित होगा। नोट के अगले एवं पिछले भाग में रुपए का चिह्न अंकित होगा। इसके साथ ही पिछले भाग में मुद्रण वर्ष 2014 अंकित होगा। नए नोए की डिजाइन इसी श्रृंखला के तहत पूर्व में जारी दस के नोट के समान होगी। इसके पूर्व जारी किए गए सभी नोट भी वैध मुद्रा रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक अजीत प्रसाद ने जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 18.2.2015)

पॉलिसीधारकों को ई-मेल आईडी देना अनिवार्य

एलआईसी पॉलिसीधारकों को अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य हो गया है। इसके बिना नई पॉलिसी नहीं हो पाएगी। जिन लोगों ने पहले से एलआईसी की पॉलिसी ली है उन्हें भी यह सूचना भेजी जा रही है कि के जल्द से जल्द अपनी पॉलिसी में ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर की इंट्री करा लें। नए नियम के अनुसार, पॉलिसीधारकों को ई-मेल आईडी एवं मोबाइल के माध्यम से पॉलिसी संबंधित जानकारी दी जाएगी। बकाया प्रीमियम, प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि, जमा करने की राशि एवं पॉलिसी पूरा होने की जानकारी इसके माध्यम से दी जाएगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 18.2.2015)

दूरभाष संख्या : 0612-2506276
फैक्स : 2506632

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
क्षेत्रीय कार्यालय, भविष्य निधि भवन, रोड नं.-6 बिहार, पटना-800001

नियोक्ता कृपया ध्यान दें

सभी नियोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के पारा 36 उप पारा (7) के तहत आवृत्त सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं द्वारा ऑनलाईन प्रपत्र 5ए विवरणी भरना अनिवार्य कर दिया गया है।

अत: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, बिहार क्षेत्र के आवृत सभी प्रतिष्ठानों को सूचित किया जाता है कि वे अपने प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठानों/शाखा कार्यालयों के प्राधिकृत अधिकारी/अधिकारियों का विवरणी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रपत्र संख्या 5ए में स्वयं विधिवत ऑनलाईन भरकर उसकी एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करायें। जो प्रतिष्ठान स्वयं प्रपत्र 5ए ऑनलाईन नहीं भर पा रहे हैं व अपने नियोक्ता /प्राधिकृत अधिकारी का पैन कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति एवं प्रतिष्ठान /नियोक्ता का लौगिंन आई. डी. के साथ भविष्य निधि कार्यालय में आकर सूचना सेवा अनुभाग में संपर्क कर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

यदि कोई प्रतिष्ठान दिनांक 31.3.2015 तक प्रपत्र 5ए ऑनलाईन नहीं भरते हैं, तो वैसे प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 14 के तहत मुकदमा दर्ज की जायेगी इसके लिये नियोक्ता स्वयं जिम्मेवार होंगे।

स्मरण रहे कि वैसे प्रतिष्ठान जो पूर्व में मैनुअली प्रपत्र 5ए जमा कराये हैं उन्हें भी पुन: ऑन लाईन भरकर कार्यालय को उसकी एक प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करानी है।

इस संबंध में किसी प्रकार की विशेष सहायता के लिए क्षेत्रीय कार्यालय के तृतीय तल पर उपलब्ध श्री प्रशांत कुमार, सहायक निदेशक (सूचना सेवा) से संपर्क कर कार्य पूर्णता में अनावश्यक विलम्ब से बच सकते हैं।

(एस. के. झा)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार क्षेत्र
बिहार, पटना

(साभार : हिन्दुस्तान, 27.2.2015)

सुकन्या अकाउंट, एक नजर

- 0 से 10 साल तक की बच्चियों का बैंक अकाउंट खोला जा सकता है। इसमें 9.1 प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा। (सेविंग अकाउंट में करीब 4 प्रतिशत और रेकरिंग डिपॉजिट में 8.4 प्रतिशत ब्याज मिलता है।)
- इसमें आयकर की धारा 80 सी के तहत आयकर में छूट दी जाएगी।
- अकाउंट खोलने के लिए बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, माता या पिता का पहचान पत्र और घर के पता का डॉक्यूमेंट जमा करना होगा।
- अकाउंट में एक साल में एक हजार से लेकर 1.5 लाख रुपये तक जमा किये जा सकते हैं।
- अकाउंट में रुपये 14 सालों तक जमा करना है।
- बच्ची की उम्र 18 साल होने पर कुल जमा राशि का 50 फीसदी निकाला जा सकता है।
- 21 साल बाद योजना मैच्योर होगी, जब पूरी राशि निकाली जा सकेगी।
- अकाउंट में समय पर रुपया जमा नहीं करने पर 50 रुपया की पेनाल्टी भी लगेगी।

(साभार : दैनिक जागरण, 18.2.2015)

बधाई

चैम्बर के सदस्य श्री निर्मल झुनझुनवाला बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के सत्र 2015-17 के प्रादेशिक अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। चैम्बर की ओर से श्री झुनझुनवाला को हार्दिक बधाई।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा चैम्बर प्रांगण में संचालित नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट

चैम्बर प्रांगण में स्थापित नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र जो फरवरी 2014 से प्रारंभ हुआ था। उसमें महिलाओं को सिलाई, कटाई, मेंहदी, बैग बनाने सहित कई तरह के प्रशिक्षण दिए गए। अब तक दो-दो पालियों में चार बैच में करीब 350 महिलाओं को तीन महीनें का उपरोक्त प्रशिक्षण दिया गया। पाँचवां बैच 10 फरवरी, 2015 से प्रारंभ हो चुका है। प्रशिक्षण केन्द्र की को-ऑर्डिनेटर डा० गीता जैन, आधार महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति हैं।

श्री मुकेश जैन, चेयरमैन, स्किल डेवलपमेंट उप-समिति ने बताया कि इस सिलाई-कटाई आदि के प्रशिक्षण के अतिरिक्त चैम्बर ने महिलाओं को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण भी देने का निर्णय लिया है, जो अप्रैल 2015 के प्रथम सप्ताह से शुरू किया जाएगा। कम्प्यूटर के प्रशिक्षण के लिए 150 महिलाओं का आवेदन जमा हो चुका है। श्री जैन ने आगे बताया कि चैम्बर की तरफ से 1 अगस्त, 2014 को प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित, जरूरतमंद एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वरोजगार हेतु 11 सिलाई मशीनें प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त जुलाई 2014 तक प्रशिक्षित महिलाओं को अगस्त 2014 में और दिसम्बर 2014 तक प्रशिक्षित महिलाओं को 29 दिसम्बर, 2014 को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए थे।

पासपोर्ट का कंप्लेन नंबर करेगा 'मदद'

मंत्रालय के अफसरों से लाइव चैट कर सकेंगे शिकायत करने वाले

विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। वे अब किसी समस्या और मदद के लिए अपने पासपोर्ट को टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने ऐसी समस्याओं के हल के लिए 'मदद' नाम से विशेष सेवा आरंभ की है। इसमें की जाने वाली शिकायत पासपोर्ट नंबर से संबद्ध होगी। यह संबंधित देश के दूतावास तक जाएगी और तुरंत मदद मिलेगी। इस प्रक्रिया में कई स्तर पर मॉनिटरिंग भी होती रहेगी।

इस खास पोर्टल को हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लॉन्च किया। विभाग की वेबसाइट passportindia.gov एवं mygov. in पर 'मदद' नाम से लिंक दी गई है। इसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) के छह देशों के साथ-साथ मलेशिया के लिए खास तौर पर शुरू किया गया है। विदेशों में करीब दो करोड़ भारतीय रहते हैं। इनमें से 57 लाख खाड़ी देश व मलेशिया में हैं। मंत्रालय के संयुक्त सचिव मुक्तेश परदेशी ने बताया कि यह सुविधा विदेशों में रह रहे भारतीयों की दिक्कतों को दूर करेगा।

ऐसे ले सकते हैं लाभ : • 'मदद' लिंक पर लॉग इन • पासपोर्ट नंबर देते ही शिकायत पासपोर्ट से संबद्ध हो जाएगी • शिकायत की प्राथमिकता कलर कोड आधारित है। संवेदनशील मामलों को प्राथमिकता • शिकायतकर्ता इस पोर्टल पर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लाइव चैट कर सकेंगे • विदेश से स्वजन की पार्थिव शरीर स्वदेश लाने के मामले में 'मदद' तुरंत उतलब्ध।

(साभार : दैनिक भास्कर, 24.2.2015)

EDITORIAL BOARD

Editor
O. P. Tibrewal
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org
Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296